Sick NTC Mills

104. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a)whether it is a fact that a strategy is being worked out for the turn around of 119 sick mills of the National Textiles Corporation;

(b)if so, the broad details of the strategy, including the time-frame fixed, if any;

(c) whether suitable steps have been initiated to safeguard the interest of the workers; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) to (d) On the basis of a unit-wis: .iability study made by NTC, Government is considering a revised turn around strategy for the viable mills of NTC, keeping in view the BIFR norm of the net worth of these mills turning positive, within the period prescribed by BIFR. The interest of the workers will be kept in view in the revival plan.

Payment of cotton dues by NTC

105. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a)whether Government are aware that the National Textile Corporation has to pay to Maharashtra State Cooperative Cotton Federation a sum of Rs. 174.19 crores or so towards payment of price of cotton purchased from the Federation by NTC;

(b)the: period for which this payment is outstanding;

(c) the reasons for delay in payment; and

(d) by when NTC would pay these dues?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) and (b) An amount of Rs. 136.72 crores is outstanding towards cotton dues to Maharashtra State Cooperative Cotton Federation as on 31.3.1998. This amount is outstanding from 1—6 years depending upon the financial constraints being faced by each mill.

(c) and (d) Cotton is purchased by the NTC on credit terms. Therefore, certain outstanding dues remain to be paid at any given point of time. Due to acute shortage of working capital and losses suffered by NTC, the payment of cotton dues to the Federation has fallen into arrears. NTC is expected to clear the outstanding dues on availability of funds after the rehabilitation package is put into operation as per BIFR approval. The cases of 8 out of 9 NTC subsidiaries are presently under reference to the BIFR.

Additional Quota of Cotton for Export by Maharashtra

106. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a)whether Government have received a request from the Maharashtra Government in September, 1997 to sanction additional quota of 2 lakh bales of cotton for export;

(b)if so, the action taken thereon;

(c) the reasons for delay in sanctioning this quota; and

(d) by when the quota would be released?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) Yes Sir.

(b) to (d) An export quota of 0.75 lakh bales of cotton was released to the Maharashtra State Cooperative Cotton Growers' Marketing Federation Ltd. on 19th September, 1997. The export quota of cotton is released by the Government from time to time after taking into account all relevant factors, including estimated production availability, domestic demand and likely surplus of cotton as well as price trends etc. As on 21.5.1998

the Maharashtra State Federation had not been able to effect any exports against the quota of 0.75 lakh bales allotted to it for the cotton year 1997-98.

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत कपड़ा मिले

107. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात में कितनी कपड़ा मिलों का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करता है;

(ख) विगत तीन वर्षो के दौरान निगम को इन मिलों से कुल कितनी धनराशि का लाभ या हानि हुई है;

(ग) क्या निगम ने रुग्ण मिलों अथवा लगातार घाटे में चल रही मिलों को पुनरुजीविति करने तथा कपड़ा मजदूरों के उद्धार के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसी मिलों के प्रबंधन में कामगारोम को भागीदारी देने पर क्या विचार किया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) एन टी सी के अधीन उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में राष्ट्रीयकृत मिलों की संख्या क्रमश: एक, सात तथा ग्यारह है। पिछले तीन वर्षो के दौरान इन 19 मिलों को हुए निवल घाटे की कुल राशि निम्नानुसार है;

वर्ष	निवल घाटा (करोड़ रु.)
95-96	116.63
96-97 (अनंतिम)	153.27
97-98 (अनंतिम)	148.02

(ग) निवल पूंजी के काम होने के कारण एन टी सी (एम.पी., गुजरात तथा डब्ल्यु जी ए जी एंड ओ) सहित एन टी सी के 9 सहायक निगमों में से 8 के मामले बी आई एफ आर को भेजे गए हैं,जिसने उन्हें रुग्ण घोषित कर दिया है। सरकार ने इन मिलों के लिए एक पुनर्वासन योजना बनाई हैं तथा उसे बी आई एफ आर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। पुनर्वासन के लिए निधियों की व्यवस्था एन टी सी की मिलों कि बेशी भूमि तथा परिसम्पत्तियों की बिक्री से की जानी थी। बी आई एफ आर ने यह पाया की एन टी सी (एम.पी.), एन टी सी (गुजरात) और एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी एंड ओ) सहित चार सहायक निगमों के मामलों में पुनर्वासन योजना व्यवहार्य नहीं है और इसीलिए इन चार सहायक निगमों को बंद करने के लिए कारण बताओं नोटिस-जारी किए हैं। तथापि, जी आई एफ आर से अनुमोदित न मिलने तथा बिक्री की आय से निधियां उपलब्ध न होने के कारण पुनर्वास योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। सरकार एन टी सी द्वारा किए गए एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर एन टी सी की अर्थक्षम मिलों के लिए संशोधित सर्वागींण सुधार नीति पर विचार कर रही है।

(घ) उड़ीसा, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में स्थिति 19 मिलों में से 17 मिलों मे एन टी/सी इस समय प्रबंधन में कामगारोम की सहभागिता की योजना क्रियान्वित कर रहा है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के स्वामित्व में अधिवेशन भूमि

108. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में कुल कितनी अधिशेष भूमि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत बंद पड़ी मिलों के स्वामित्व में है;

(ख) इस अधिशेष भूमि का बाजार मूल्य क्या है और क्या इस भूमि पर अवैध कब्जा करने का कोई शिकायतें सामने आयी हैं;

(ग) क्या सरकार राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से इस अधिशेष जमीन को बेचने का विचार रखती है; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई बातचीत की है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) एन.टी.सी. के पास महाराष्ट्र और गुजरात में कुल बेशि क्षेत्र 453.76 एकड़ है जिसका मूल्य 1984 करोड़ रुपए है। एन.टी.सी. की महाराष्ट्र और गुजरात में कोई भी मिल बंद नहीं है। एन.टी.सी. की मिलों की भूमि पर कुछ अतिक्रमण करने की सूचना प्राप्त हुई है तथा उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) एन.टी.सी. की मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए निधियां जुटाने की दृष्टि से एन.टी.सी. की बेशी भूमि बेचने का प्रस्ताव है। यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है तथा इस संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श भी किया गया है।